दक्षिण-दक्षिण

जुलाई 2026

विश्व के बहुसंख्य लोगों के लिए एक सही नज़रिया बनाने की कोशिश

प्रख्यात फ़लस्तीनी चित्रकार मलक मत्तार द्वारा बनाया गया एक फ़लस्तीनी औरत का चित्र।

हमारे लिए इस चित्र के मायने हैं, "सबसे कमज़ोर लोगों की सामूहिक ताक़त जो हासिल करेगी सबके लिए अमन और इंसाफ़।"

विषय सूची

ब्रिक्स: उभरता बहुपक्षीय मंच

भारत में ब्रिक्स बैठकों का घटनाक्रम

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठकः एक टिप्पणी

इतिहास के झरोखे सेः बांडुंग सम्मेलन

विशेष: इंडोनेशिया

ब्रिक्स सदस्य देशों की एक झलक

अंतिम पृष्ठ: कविता और तस्वीरः नाज़िम हिकमत और अब्बास मोमानी

संपादकीय

यह समाचार एवं विचार पत्र दुनिया में तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से निकाला जा रहा है। दक्षिणी दुनिया यानि 'ग्लोबल साउथ' का विस्तार हो रहा है, वह अपनी बात मज़बूती से कह रहा है और इस दुनिया को चलाने के तौर-तरीकों में बदलाव और भागीदारी का दावा पेश कर रहा है।

हम इस न्यूजलेटर के और अधिक अंक प्रकाशित करने और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अधिक लोगों तक पहुँचाने और सामग्री को बेहतर बनाने के संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यह कार्य समाज को शिक्षित करने के गैर-लाभकारी उद्देश्य से किया जा रहा है। तक़रीबन सभी तस्वीरें इंटरनेट और खुले स्रोतों से ली गई हैं।

संपादकीय टीम: जया मेहता, विनीत तिवारी, सुधीर सजल, मोहित।
संपर्क: joshiadhikari@gmail.com | www.jaiss.org.in

ब्रिक्स: एक उभरता बहुपक्षीय मंच

सन् 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चिह्नित किया था और सुझाव दिया था कि इन्हें जी-7 में शामिल कर 'ग्लोबल नॉर्थ' को और समावेशी बनाया जाए। यह विडंबना ही है कि उन उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा गठित समूह ब्रिक्स अब ग्लोबल नॉर्थ के बरअक्स ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापार और विकास का एक वैकल्पिक मंच प्रदान करने वाला संगठन बन चुका है।

BRIC (ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन) का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ़्रीका पाँचवाँ सदस्य बना और संगठन का नाम BRICS हो गया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद गठित इस समूह ने अपने पहले शिखर सम्मेलन में माँग की कि उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए। साथ ही एक पारदर्शी, समावेशी, न्यायसंगत और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना पर भी ज़ोर दिया गया। ब्रिक्स देशों की ये माँगें ब्रेटन वुड्स वित्तीय संस्थाओं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा नहीं मानी जा सकीं, क्योंकि ये संस्थाएँ ग्लोबल नॉर्थ ने साम्राज्यवादी शोषण को आसान बनाने के लिए बनाई थीं।

तब ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल साउथ के देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र संस्थाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया। 2014 में ब्राज़ील के फ़ोर्टालेज़ा में हुए शिखर सम्मेलन में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एक आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA) की स्थापना के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनडीबी का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में बुनियादी ढाँचे और टिकाऊ विकास परियोजनाओं को सहायता देना है, जबकि CRA चालू खाता घाटे से उबरने के लिए आकस्मिक ऋण देने के लिए बनाई गई थी। एनडीबी 2015 से काम कर रहा है, लेकिन CRA अभी तक क्रियाशील नहीं हुई है।

एनडीबी वास्तव में मौजूदा विकास बैंकों से अलग है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो ग्लोबल नॉर्थ की किसी सहायता या वर्चस्व से मुक्त है। यह ग्लोबल साउथ की उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा संचालित विकास बैंक है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। संस्थापक सदस्यों के अलावा बांग्लादेश, मिस्र, सं. अरब अमीरात और उरुग्वे एनडीबी के सदस्य बन चुके हैं। उज़्बेकिस्तान, कोलंबिया और इथियोपिया संभावित सदस्य हैं। ज़िम्बाब्वे भी जल्द ही एनडीबी में शामिल होने वाला है।

एनडीबी की शुरुआती अधिकृत पूँजी 100 अरब अमेरिकी डॉलर है जो 10 लाख शेयरों में विभाजित है। शुरुआती अभिदत्त (subscribed) पूँजी 50 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें पाँच संस्थापक सदस्यों की बराबर भागीदारी है। एनडीबी के समझौते में तय है कि हर सदस्य का एक ही वोट होगा और किसी भी सदस्य को वीटो का अधिकार नहीं होगा।

एनडीबी का ज़ोर ब्रिक्स देशों, अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं और आम तौर पर विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और टिकाऊ विकास परियोजनाओं को सहायता देने पर है। एनडीबी के ऋण डॉलर में तथा उधार लेने वाले देश की स्थानीय मुद्रा में भी दिए जाते हैं। 2022 तक संस्थापक सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत 71 परियोजनाओं के लिए 30.23 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी थी। इसके बाद बांग्लादेश की अनेक परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता दी गई। बांग्लादेश सितंबर 2021 में एनडीबी का सदस्य बना। कोविड-19 के दौरान एनडीबी ने विभिन्न देशों की मदद के लिए ऋण की व्यवस्था भी की थी।

वर्ष 2023 के ऐतिहासिक जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह का विस्तार हुआ और छः नये सदस्य शामिल किए गए — अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बाद में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने फ़ैसला किया कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। वर्ष 2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन में 36 देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित छः अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में ब्रिक्स मंच का और विस्तार किया गया। इस बार किसी देश को पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इन तेरह देशों को ब्रिक्स भागीदार बनने का आमंत्रण दिया गया — अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्किये, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम। अल्जीरिया और तुर्किये भागीदार सदस्य के रूप में नहीं जुड़े। बाद में जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता दी गई। 2026 में ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य और 10 भागीदार सदस्य हैं। यह विस्तार यहीं रुकने वाला नहीं है। अनेक और देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई है।

ग्यारह सदस्यों वाला विस्तृत ब्रिक्स दुनिया की 45 प्रतिशत जनसंख्या, वैश्विक GDP के 37 प्रतिशत (क्रय शक्ति समानता के अनुसार) और वैश्विक तेल उत्पादन के 45 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और तकनीकी रूप से सक्षम है। व्यावहारिक दृष्टि से, ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स एक मज़बूत संस्थागत आधार प्रदान करता है। संगठनात्मक रूप से, ब्रिक्स एक विशिष्ट संस्था है। ग्लोबल साउथ के देश आकार में तो भिन्न हैं ही, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी पृष्ठभूमि में भी एक-दूसरे से बहुत भिन्नता रखते हैं। इतनी विविधता वाले देशों को एक मंच पर लाकर लोकतांत्रिक ढंग से, अधिकांश मामलों में सर्वसम्मति पर ज़ोर देते हुए संचालित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

https://focusweb.org/wp-content/uploads/2020/05/JM_The-Struggle-for-Alternatives-ed.pdf

भारत में ब्रिक्स बैठकों का घटनाक्रम

9 फरवरी 2026, नई दिल्लीः पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक

भारत की 2026 की अध्यक्षता की आधिकारिक शुरुआत हुई; आगामी कार्यसूची के लिए पारस्परिक व्यवस्थाएँ तय की गईं।

24 अप्रैल 2026, नई दिल्ली — ब्रिक्स उप-विदेश मंत्रियों और मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ़्रीकी देशों (MENA) के विशेष दूतों की बैठक

प्रतिनिधियों ने गाज़ा की स्थिति, फ़िलीस्तीन के मुद्दे, मानवीय सहायता, तथा लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, लीबिया और सूडान में जारी संघर्षों पर विचार-विमर्श किया। पश्चिम एशिया के संघर्ष पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के कारण सदस्य देश सर्वसम्मति पर नहीं पहुँच सके। भारत ने ब्रिक्स उप-विदेश मंत्रियों की बैठक पर अध्यक्ष का वक्तव्य जारी किया।

11 मई 2026, नई दिल्ली — दूसरी ब्रिक्स शेरपा बैठक

14–15 मई 2026, नई दिल्ली — विदेश मंत्रियों की बैठक

प्रतिनिधियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों, वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार तथा अनेक अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक पर एक टिप्पणी आगे के पृष्ठों में दी गई है।

3 जून 2026, पुरी (ओडिशा) — आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) बैठक

DRR (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) कार्यसमूह की बैठक पुरी में हुई, जो इस क्षेत्र में पहली आमने-सामने की बैठक थी। बैठक में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तपोषण, बहु-संकटपूर्व चेतावनी प्रणाली, लचीला बुनियादी ढाँचा, प्रकृति-आधारित समाधान, तथा आपदा सहनशीलता को मज़बूत बनाने के लिए विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार के उपयोग जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने रामचंडी में ओडिशा राज्य आपदा मोचन बल (ODRAF) द्वारा जल बचाव तैयारियों को भी देखा।

12–13 जून 2026, इंदौर (मध्य प्रदेश) —कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक

कृषि मंत्रियों की बैठक में 'इंदौर घोषणापत्र' को अपनाया गया। घोषणापत्र में उल्लिखित प्रमुख पहलों में शामिल हैं — जलवायु सहनशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क, ब्रिक्स एग्रिन (कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क) का शुभारंभ, बीज प्रणाली में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच की स्थापना और तकनीक-संचालित खेती के लिए ब्रिक्स डिजिटल कृषि नेटवर्क की स्थापना।

22–23 जून 2026, नई दिल्ली —ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की 16वीं बैठक

इस बैठक में 'आज की दुनिया के सामने ग़ैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियाँ' विषय पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आतंकवाद, आपूर्ति शृंखला की मज़बूती और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में व्यावहारिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

23–24 जून 2026, बेंगलुरु — अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक (HOSA)

यह बैठक ISRO द्वारा आयोजित की गई। सदस्यों ने मुख्य रूप से मलबा-मुक्त अंतरिक्ष अभियानों, दीर्घकालिक टिकाऊ संचालन और ब्रिक्स स्पेस इकॉनमी फ्रेमवर्क की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। प्रस्तावित ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के लिए संदर्भ की शर्तें तय करने में प्रगति हुई।

25–26 जून 2026, गुरुग्राम (हरियाणा) —ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक

बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई और 'ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस फॉर स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज' का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। प्रतिनिधियों ने वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन की निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए स्वच्छ तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। सीमापार ऊर्जा व्यापार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक: एक टिप्पणी

विदेश मंत्रियों की बैठक 14 और 15 मई 2026 को नई दिल्ली में हुई। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, सिवाय चीन के। उसी समय ट्रम्प के चीन यात्रा पर होने के कारण चीनी विदेश मंत्री दिल्ली नहीं आ सके। चीन का प्रतिनिधित्व भारत में चीनी राजदूत ने किया। भागीदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।

उप-विदेश मंत्रियों की बैठक की तरह ही, इस बैठक में भी संयुक्त घोषणापत्र जारी नहीं किया जा सका। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर ईरान और सं. अरब अमीरात के परस्पर विरोधी रुखों के कारण प्रतिभागी सर्वसम्मति पर नहीं पहुँच सके। इसलिए विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का अध्यक्षीय वक्तव्य और परिणाम दस्तावेज़ जारी किया। बैठक के एजेंडे का दायरा व्यापक था, जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर रुख़, वैश्विक शासन में सुधार, जलवायु संकट, डिजिटल दुनिया, कृषि व खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मुद्दा-आधारित सहयोग और समन्वय शामिल था।

अध्यक्षीय वक्तव्य में ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले और उसके जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य', इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले का भी कोई ज़िक्र नहीं हुआ। वक्तव्य में केवल इतना कहा गया — 'पश्चिम एशिया / मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति के बारे में कुछ सदस्यों के अलग-अलग विचार थे। ब्रिक्स सदस्यों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी दी और विभिन्न दृष्टिकोण साझा किए।'

इन मुद्दों पर सर्वसम्मति न बन पाने को पश्चिमी मुख्यधारा मीडिया ने विस्तृत ब्रिक्स में दरार के संकेत के रूप में पेश किया है। कुछ अन्य लोगों ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के बारे में बैठक में स्पष्ट साम्राज्यवाद-विरोधी रुख़ न अपनाने पर निराशा जताई है। लेकिन ये विचार उस मूलभूत विशेषता को ध्यान में रखे बिना प्रकट किए जा रहे हैं जो इस समूह को परिभाषित करती है। ब्रिक्स सदस्य देशों का मंच किसी राजनीतिक गुटबंदी पर आधारित नहीं है।

यह मंचअलग-अलग प्राथमिकताओं, प्रतिस्पर्धी हितों और कभी-कभी राजनीतिक तनाव और सैन्य संघर्षों वाले सदस्य देशों के बीच संवाद और सर्वसम्मति को सुविधाजनक बनाता है। एक मंच के रूप में ब्रिक्स इन जटिलताओं से सफलता-पूर्वक निपटता आया है। साथ ही, ब्रिक्स बैठकों में शांति, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय सहायता आदि मुद्दों पर जो सर्वसम्मति बनती है, वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

दिल्ली में संपन्न विदेश मंत्रियों की बैठक में मंत्रियों ने इजराइल अधिकृत फ़िलिस्तीन की स्थिति, गाज़ा पर हो रही

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री

लगातार बमबारी, मानवीय सहायता को मनाही और भुखमरी को नरसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। फ़िलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय और घर-वापसी के उनके वैध अधिकार दिलाने के प्रति समर्थन को दृढ़ता से दोहराया गया। इसका अर्थ होगा - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 1967 की सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फ़िलीस्तीनी राज्य की स्थापना, जिसमें गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक शामिल हों और पूर्वी येरुशलम उसकी राजधानी हो।

अध्यक्षीय वक्तव्य में फ़िलीस्तीन के संबंध में कार्रवाई की माँग करते हुए एक और खंड शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि गाज़ा पट्टी फ़िलीस्तीन के अधिकृत क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए गाज़ा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फ़िलिस्तीनी अधिकार क्षेत्र के तहत लाया जाना चाहिए। मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि वे फ़िलीस्तीनियों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फ़िलीस्तीनी प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यों में सहायता करें। (एक सदस्य ने इस खंड पर आपत्ति जतायी।)

इस मंत्रिस्तरीय बैठक ने लेबनान में तत्काल युद्धविराम लागू करने की माँग की और इजराइल द्वारा लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की। मंत्रियों ने लेबनान पर क़ाबिज़ इज़राइली सैन्य बलों की वापसी की माँग की।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से समुद्री व्यापार का निर्बाध प्रवाह सभी देशों के लिए एक प्रमुख चिंता बन गई है। बैठक में लाल सागर और बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता के संबंध में नौवहन अधिकार सुनिश्चित करने का प्रश्न उठाया गया। मंत्रियों ने इस दिशा में कूटनीतिक प्रयासों को तेज़ करने की सिफ़ारिश की। इस संवाद में यमन में शांति वार्ता को उसकी समग्रता में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक में खाद्य सुरक्षा और बुनियादी

सेवाओं तक पहुँच सहित यमन के मानवीय संकट को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। (एक सदस्य देश ने इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई।) बैठक ने मनमाने ढंग से लगाए गए एकतरफ़ा आर्थिक और द्वितीयक प्रतिबंधों पर नाराज़गी व्यक्त की। ऐसे प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के सिद्धांतों को कमज़ोर करते हैं। मंत्रियों ने दोहराया कि ब्रिक्स देश ऐसे प्रतिबंध न तो लगाते हैं और न उनका समर्थन करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत नहीं हैं।

मंत्रिस्तरीय बैठक ने प्रतिबंधों के कारण क्यूबा की अर्थव्यवस्था का गला घोंटे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और माँग की कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के अनुसार तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध हटाए जाएँ।
राजनीतिक रूप से इन संवेदनशील विषयों के अलावा वैश्विक शासन में सुधार जैसे ग़ैर-विवादास्पद मुद्दे पर व्यापक सर्वसम्मति और उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देखने को मिली। सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक आदि में उभरते बाज़ार और विकासशील देशों (Emerging Markets and Developing Countries या EMDC) का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की माँग की।

मंत्रियों ने एक ग़ैर-भेदभावपूर्ण, खुली, न्यायसंगत, पारदर्शी, उचित, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मज़बूती देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ब्रिक्स देशों और अन्य देशों के बीच सीमापार भुगतान को तेज़, कम लागत वाले, अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के प्रयासों के महत्त्व पर ज़ोर दिया, जिससे व्यापार और निवेश का प्रवाह बढ़ सके। इस संदर्भ में उन्होंने ब्रिक्स सीमापार भुगतान पहल पर चर्चा जारी रखने को प्रोत्साहित किया। मंत्रियों ने माना कि ब्रिक्स देश वैश्विक खाद्य उत्पादन में प्रमुख भागीदार हैं। कृषि उत्पादकता और स्थायित्व बढ़ाने, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में उन्होंने ब्रिक्स के भीतर अनाज व्यापार मंच (ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज) की स्थापना की पहल के निरंतर विस्तार और उसके बाद उसमें अन्य कृषि उत्पादों एवं वस्तुओं को शामिल करने की सराहना की।

जलवायु संकट के प्रश्न पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ। मंत्रियों ने पेरिस समझौते और UNFCCC में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। वैश्विक तपन को कम करने लिए जैव विविधता, वन आवरण, लचीला बुनियादी ढाँचा आदि सहित अनेक पहलों पर चर्चा हुई। बैठक में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भी विचार-विमर्श हुआ। मंत्रियों ने दोहराया कि तकनीकी प्रगति का उपयोग शांतिपूर्ण और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अधिक समावेशी, सुलभ, टिकाऊ और साझे तरीक़े से किया जाना चाहिए।

मंत्रियों ने ब्रिक्स सहयोग में भागीदार देशों के मूल्यवान योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने आपसी सम्मान और समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, समावेशिता, निरंतरता, पूर्ण परामर्श और सर्वसम्मति की भावना के अनुरूप ब्रिक्स को मज़बूत और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

ब्रिक्स में शामिल सभी देश एक जैसी सोच और राजनीतिक विचारधारा या एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था के नहीं हैं। सबके साथ आने का मक़सद भी दुनिया में कोई बेहतर व्यवस्था कायम करना नहीं होकर अपने हित और लाभ सुरक्षित करना है। ब्रिक्स की विविधतापूर्ण संरचना और केवल सर्वसम्मति से आगे बढ़ने का उसका नियम, समूह को कोई उग्र रास्ता अपनाकर एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक विश्व व्यवस्था की ओर बड़ी छलाँग लगाने नहीं देता। लेकिन यह समूह के भीतर एकजुटता बनाये रखता है और ख़ुद को ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सच्चे लोकतांत्रिक मंच के रूप में प्रस्तुत करता है। यह धीरे-धीरे स्थिर क़दमों से एक नयी विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ता रहता है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघ्ची ने 15 मई 2026 को नयी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्रीय संघर्षों का कोई सैन्य समाधान नहीं है और बातचीत के ज़रिए समझौता ही आगे का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय संकट को स्थिर करने में भारत के रचनात्मक योगदान का हार्दिक स्वागत करेगा।

इतिहास की एक झलक: बांडुंग सम्मेलन

बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया, 1955 तस्वीरः इंटरनेट से

द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। यह युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था में अमेरिकी एकाधिकार की घोषणा थी।

यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों और उत्तरी दुनिया के देशों (ग्लोबल नॉर्थ) के नये उभरे साम्राज्यवादी विश्व ने निर्णय लिया कि वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे। वे युद्धों के बीच के समय की तरह आर्थिक मोर्चे पर पूर्ण अराजकता भी नहीं चाहते थे। तब यह निर्णय लिया गया कि एक नियम-आधारित विश्व व्यवस्था स्थापित की जाए जो साम्राज्यवादी विश्व के लाभ के लिए काम करे। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाये रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्थितियों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। पूँजीवादी विश्व में आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तैयार की गई थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से तत्कालीन उपनिवेशों की अपने औपनिवेशिक स्वामियों से मुक्ति की शुरुआत भी हुई। दक्षिणी दुनिया (ग्लोबल साउथ) के नवमुक्त देश, और जो स्वतंत्र होने की उम्मीद कर रहे थे, उन सभी देशों ने आशा की कि संयुक्त राष्ट्र उनकी संप्रभुता की रक्षा करेगा, और ब्रेटन वुड्स संस्थान वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा तकनीकें साझा करके उनके विकास में सहायक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ और 1953 तक जारी रहा। अमेरिका ने 1951 के अंत तक कोरिया के उत्तरी भाग में मौजूद बुनियादी ढाँचे के हर इंच को बमबारी से तबाह कर दिया था। पुरानी औपनिवेशिक शक्तियों ने अभी भी अपने उपनिवेशों पर सैन्य पकड़ बनाए रखी थी, और अमेरिका सोवियत संघ और चीन को घेरने के लिए इंडो-चाइना इलाक़े में मौजूद देशों के साथ नये सैन्य गठबंधन बना रहा था। अमेरिका द्वारा चीन को बार-बार धमकी दी गई कि यदि ताइवान के मामले में चीन द्वारा कोई सैन्य हस्तक्षेप किया गया, तो अमेरिका परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा।

तीसरी दुनिया की विकास आकांक्षाओं को दरकिनार कर अमेरिकी डॉलर को विश्व मुद्रा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार, अमेरिका ने पूँजीवादी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ब्रेटन वुड्स संस्थान मुख्यतः यूरोप के पुनर्निर्माण में लगे थे। तीसरी दुनिया की विकास आकांक्षाओं के लिए उनके पास बहुत कम गुंजाइश थी।

यह वह पृष्ठभूमि थी जिसमें नये-नये आज़ाद हुए एशियाई और अफ़्रीकी देशों का एक सम्मेलन 18-24 अप्रैल 1955 को बांडुंग (इंडोनेशिया) में हुआ। उनतीस एशियाई और अफ़्रीकी देशों के प्रमुखों के साथ-साथ उन उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी बांडुंग में एकत्र हुए, जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाये थे, लेकिन जहाँ आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू (भारत), चाउ एन-लाइ (चीन), यू-नू

(बर्मा), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया) और अनेक अन्य लोगों ने भाग लिया। ये नेता, जो अपने-अपने देशों में स्वतंत्रता संग्राम से उभरे थे, जानते थे कि औपनिवेशिक डिजाइन और उसके साथ जुड़ी हिंसा उत्तर-औपनिवेशिक युग को आतंकित करती रहेगी। एक नयी विश्व व्यवस्था बनाने के लिए एशिया और अफ़्रीका की नवमुक्त दुनिया द्वारा एकजुट होकर मज़बूत प्रतिरोध करने की आवश्यकता थी।

सुकर्णो ने सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, 'एशिया और अफ़्रीका तभी समृद्ध होंगे जब वे एकजुट होंगे। यहाँ तक कि पूरे विश्व की सुरक्षा भी एकजुट एशिया और अफ़्रीका के बिना क़ायम नहीं रह सकती। मुझे आशा है कि यह सम्मेलन मानव जाति को मार्गदर्शन देगा, मानव जाति को वह रास्ता दिखाएगा जो उसे सुरक्षा और शांति प्राप्त करने के लिए अपनाना चाहिए। मुझे आशा है कि यह इस बात को प्रमाणित करेगा कि एशिया और अफ़्रीका का पुनर्जन्म हुआ है, बल्कि एक नये एशिया और एक नये अफ़्रीका ने जन्म लिया है।' सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श मुख्य रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, तथा सभी जातियों और सभी राष्ट्रों की समानता पर केंद्रित थे। इस संदर्भ में, एशिया के चारों ओर निर्मित सैन्य गठबंधनों और ठिकानों, तथा परमाणु हमलों की धमकियों की कड़ी आलोचना की गई। इस संबंध में बनाये गए दस सिद्धांतों को सम्मेलन की अंतिम घोषणा में शामिल किया गया।

उन दस सिद्धांतों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (1945) के सिद्धांतों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत की। 1955 में 76 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए संधि की तरह बाध्यकारी था। हालाँकि, लगभग अस्सी क्षेत्र, जिनमें अफ़्रीकी महाद्वीप का अधिकांश भाग और अधिकतर प्रशांत द्वीप शामिल थे, घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के औपनिवेशिक नियंत्रण में बने रहे। जैसे-जैसे देशों ने 1950 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक स्वतंत्रता प्राप्त की, वे संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल होते गए। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र तब, और अब भी सर्वसम्मति के आधार पर तैयार किया गया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसका साम्राज्यवादी देशों द्वारा शुरू से खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जाता रहा है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता और समानता के अलावा, बांडुंग सम्मेलन के विमर्शों में एक नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की भी कल्पना की गई। इसकी अंतिम घोषणा के एक खंड में ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई थी। आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए अनेक ठोस प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई। चूँकि साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों को केवल कच्चा माल उत्पादित करने के स्थलों के रूप में विकसित किया था, इसलिए वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने और निर्यात से पहले इन वस्तुओं को संसाधित करने के लिए घरेलू क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया। इन देशों में आर्थिक विकास के लिए निवेशों के वित्तपोषण हेतु विशेष संयुक्त राष्ट्र कोष स्थापित करने का भी आह्वान किया गया। आर्थिक विकास के लिए विशेष संयुक्त राष्ट्र कोष 1958 में स्थापित किया गया, जो 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) में परिवर्तित हो गया। 1964 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की स्थापना हुई।

बांडुंग सम्मेलन में सुकर्णो, 1955

बांडुंग के दस सिद्धांत

1. बुनियादी मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान;
2. सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान;
3. सभी नस्लों और छोटे या बड़े सभी देशों की समानता को मान्यता देना;
4. दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देना;
5. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार, हर देश के अपनी रक्षा (अकेले या मिलकर) करने के अधिकार का सम्मान करना;
6. बड़ी ताक़तों के हितों को साधने के लिए सामूहिक रक्षा व्यवस्थाओं की गुटबाजियों में इस्तेमाल न होना तथा दूसरे देशों पर दबाव न डालना;
7. आक्रामकता या बल प्रयोग की कार्रवाई या धमकी से बचना;
8. शांतिपूर्ण तरीक़ों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना;
9. आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देना;
10. न्याय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करना।

बांडुंग सम्मेलन कोई साधारण सम्मेलन नहीं था। यह विशिष्ट था। यह अरबों की जनसंख्या, ग्रह की लगभग आधी आबादी के प्रतिनिधियों का जमावड़ा था, जिसने वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन को चिह्नित किया। यह सम्मेलन उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत का उत्सव और मानव जाति के लिए इसके निहितार्थों पर चिंतन था। बैठक में बोलने वाले नेता अपने साथ अपने लोगों की आवाज़ लेकर आए थे, जो सदियों से ग़ुलाम, उत्पीड़ित और अपमानित थे। रोएसलान अब्दुल गनी बांडुंग सम्मेलन के महासचिव थे। उन्होंने 'बांडुंग स्पिरिट (भावना)' शब्द गढ़ा, जिसे इस प्रकार वर्णित किया गया, 'एक-दूसरे के मामलों में ग़लत तरीक़े से हस्तक्षेप किए बिना, एक-दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शांति के प्रति प्रेम, अहिंसा, भेदभाव-विरोधी और सभी के लिए विकास की भावना।' बांडुंग स्पिरिट केवल नेतृत्व के भाषणों और विचारों तक सीमित नहीं थी। यह सामान्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा लड़े गए तीसरी दुनिया के स्वतंत्रता संग्रामों के मूल्यों में निहित थी।

बांडुंग सम्मेलन के बाद 1950 और 60 के दशक में तीसरी दुनिया के देशों के अनेक सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गईं और आपसी सहयोग के लिए तीसरी दुनिया के अनेक क्षेत्रीय समूहों का गठन हुआ। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का उदय और 1964 में ग्रुप ऑफ़ 77 (जी-77) का गठन, बांडुंग भावना को आगे बढ़ाने वाले दो बड़े अनुवर्ती क़दम थे। वर्ष 1974 में नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) के प्रस्ताव विकासशील देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 1 मई 1974 को एक नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पर घोषणा को मान्यता दी।

हालाँकि, नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार अंदरूनी कमज़ोरियों और अंतर्विरोधों से भी घिरा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित प्रस्ताव किसी के लिए बाध्यकारी तो था नहीं कि विकसित देश उसे मानकर इन नवस्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए ज़रूरी अनुकूल हालात बनायें। और न ऐसा उन्होंने किया।

दूसरी तरफ़ जो जी-77 देशों का समूह था, वह अपने आप में बहुत विसंगतिपूर्ण था। उसमें तेल का निर्यात करने वाले खाड़ी के बेहद अमीर देश भी थे और अफ़्रीका के सदियों तक ग़ुलाम रहे बहुत ग़रीब देश भी। सन 1960 में तेल उत्पादक देशों ने मिलकर अपने तेल पर इंग्लैंड, फ़्रांस और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क़ब्ज़ा हटाने के लिए तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries, ओपेक) बना लिया। इससे उन्हें अपने तेल पर अपना अधिकार तो हासिल हुआ लेकिन 1973 में जब ओपेक देशों ने तेल निकालना और निर्यात करना बंद कर दिया तो तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया था। नतीजा यह हुआ कि तेल निर्यातक देशों ने तो बेशुमार लाभ कमाया लेकिन तेल आयात करने वाले ग़रीब देशों को तेल के दाम बढ़ जाने से बहुत मुश्किल हुई। उस दौर में पश्चिम एशिया के शेखों ने जो मुनाफ़ा कमाया, वह अमेरिका और यूरोप के बैंकों में जमा किया। इससे उन बैंकों के पास तरल पूँजी बढ़ गई। बैंकों में जो ज़्यादा धन आ गया, उसे उन्होंने अफ़्रीका और एशिया के उन विकासशील ग़रीब देशों को क़र्ज़ देने में इस्तेमाल किया जो पहले ही अर्थव्यवस्था के मामले में कमज़ोर थे और जिन पर तेल के दाम बढ़ने से गाज गिरी हुई थी। पश्चिमी बैंकों ने उन्हें आसान क़र्ज़ दे तो दिया लेकिन मनमानी शर्तें लगायीं। अस्सी के दशक के क़र्ज़ के उस संकट ने अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रौंद कर रख दिया था। जब वे क़र्ज़ न चुका पाने की वजह से कोई रास्ता निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के दरवाज़े पहुँचे तो आईएमएफ़ ने उन पर ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) थोप दिया। इसके तहत यह देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने और आयात-निर्यात पर से सभी प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर हुए।

1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के नेतृत्व वाला समाजवादी खेमा ढह गया। इससे नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था और एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था वाले दौर की शुरुआत हुई। विकासशील देशों पर लागू किये गए निर्यात-उन्मुख विकास मॉडल ने उन्हें आपस में सहयोग करने के बजाय एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया। क़र्ज़ और कम खर्च (अपने देश की जनता पर) की स्थिति में स्थायी रूप से फँसे विकासशील देशों के शब्दकोश से 'बांडुंग स्पिरिट' शब्द ग़ायब हो गया।

21वीं सदी की शुरुआत ने विश्व पूँजीवादी उत्पादन संरचना को एक नया मोड़ दिया। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट ने

पश्चिमी मीडिया के लिए, 1945 और 1990 के बीच दुनिया में जो कुछ भी हुआ, उसे केवल 'शीत युद्ध' का नाम ही दिया जाता है। USSR ग़ायब हो गया, और शीत युद्ध भी उसके साथ ग़ायब हो गया, इसलिए उस समय जैसी कोई भी स्थिति अब कोई मायने नहीं रखती। इसके पीछे के रवैये के बेतुकेपन और अविश्वसनीय रूप से तिरस्कारपूर्ण – यहाँ तक कि नस्लवादी पूर्वाग्रह पर विचार करें। बांडुंग सम्मेलन और उससे उभरे गुटनिरपेक्षता के सच्चे इतिहास ने प्रदर्शित किया कि एशियाई और अफ़्रीकी लोगों ने उस समय अपने द्वारा, और अपने लिए एक पहल की थी... वह गुटनिरपेक्षता वास्तव में पहले से ही वैश्वीकरण के उस मॉडल के प्रति 'गुटनिरपेक्षता' थी, जिसे साम्राज्यवादी शक्तियाँ नव-स्वतंत्र देशों पर थोपना चाहती थीं। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की पुनर्स्थापना की इस अपेक्षा के आगे झुकने से इन्कार से ही गुटनिरपेक्षता की भावना उत्पन्न हुई थी। आज, दक्षिण के देश फिर से एक साम्राज्यवादी वैश्वीकरण परियोजना का सामना कर रहे हैं जिसके वे शिकार होंगे। इस अन्यायपूर्ण अपेक्षा के आगे न झुकने की उनकी इच्छा वैश्वीकरण पर 'गुटनिरपेक्षता के पुनर्जन्म' की ज़रूरत को फिर से सिद्ध करती है।

- समीर अमीन, 'द लॉन्ग रेवोल्यूशन ऑफ़ द ग्लोबल साउथ', मंथली रिव्यू प्रेस, 2019

डॉलर-केंद्रित वित्तीय और मौद्रिक संरचना की कमज़ोरी को ज़ाहिर कर दिया। साथ ही, ग्लोबल साउथ की कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने वृद्धि की बहुत तीव्र दर दर्ज की। चीनी अर्थव्यवस्था द्वारा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ली गई बड़ी छलाँग अभूतपूर्व थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका को उन्नत आर्थिक स्थिति की ओर संक्रमण करने वाले देशों – उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पहचाना गया। ये देश एक साथ आये और ब्रिक्स का गठन किया। दो दशकों से भी कम समय में, भू-राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अमेरिका द्वारा स्थापित युद्धोत्तर साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था में अनेक दरारें पड़ चुकी हैं। साम्राज्यवादी गुट का सैन्य अतिविस्तार राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारी क़ीमत माँग रहा है। आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति काफी कमज़ोर हो गई है। वित्त का अस्थिर विशाल बुलबुला जो विश्व अर्थव्यवस्था को घेरे हुए है, किसी भी दिन फट सकता है। वर्तमान साम्राज्यवादी-नवऔपनिवेशिक विश्व व्यवस्था का अंत निकट है।

इसी दौरान ब्रिक्स भी पाँच देशों के समूह से बढ़कर 11 पूर्ण सदस्य देशों और 10 सहयोगी (पार्टनर) देशों का विस्तृत समूह बन गया। चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनिश्यटिव (बीआरआई) से क़रीब 150 देश जुड़ चुके हैं। दक्षिणी दुनिया यानि ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आपस में व्यापार और निवेश काफ़ी महत्त्वपूर्ण तरह से बढ़ चुका है। इस बदलाव में मौजूदा विश्व व्यवस्था को बदलकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था लाने का संकल्प भी शामिल लगता है। यह बीच का एक ऐसा संक्रमणकालीन दौर है जिसमें पुराना ढाँचा ढह रहा है लेकिन उसकी जगह लेने वाला नया ढाँचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। जो भी नयी संरचना बन रही है, उसका ठोस रूप अभी सामने आया नहीं है, या उसने अभी ठोस रूप लिया ही नहीं है। इतिहास के ऐसे अहम मोड़ पर यह बेहतर होता है कि मौजूदा बदलावों की प्रकृति और रुख, उनकी ताक़त और उनकी चुनौतियों को पहचानने के लिए हम और पीछे के इतिहास को भी ज़रा देखें। उन्नीस सौ पचास और साठ के दशक में नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नवस्वतंत्र देशों की संप्रभुता और समानता के अधिकार के संदर्भ में देखा गया था। इन अधिकारों की माँग व्यापक तौर पर एक ऐसी व्यवस्था के दायरे में सोची गई थी जो समाजवादी किस्म के विकास वाली हो और जनहितैषी हो - चाहे वह भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना हो या अफ़्रीका की अरुषा घोषणा। उपनिवेश रहे देशों के आज़ादी के संघर्षों में एक बड़ा आधार मेहनतकश तबके का था। इसीलिए जो नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था सोची गई, उसकी बुनियाद में मेहनतकश तबके और कामकाजी लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी शामिल थी।

आज के दौर में दक्षिणी दुनिया के देशों का साथ में आना सीधे-सीधे इस रूप में तो नहीं देखा जा सकता कि यह नव-उदारवादी विकास के ढाँचे का विकल्प तैयार करने की कोई गुटबन्दी है। दक्षिणी दुनिया के इन देशों में अनेक सरकारें तो जनपक्षीय भी नहीं कही जा सकतीं। इसलिए इन देशों के मेहनतकश लोगों, मजदूरों और किसानों के सामने भी यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के ढहने पर जो व्यवस्था उभरेगी, उसमें उनकी हैसियत और जगह क्या होगी। लेकिन इतिहास से हम इतना तो जानते ही हैं कि अगर बनने वाली नयी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए अमन और तरक़्क़ी, शांति और विकास सुनिश्चित करना है तो उसमें मेहनतकश तबके की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। इसलिए यह आवश्यक और अनिवार्य है कि बांडुंग की भावना को धरातल पर उतारा जाए।

बांडुंग सम्मेलन से पहले अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। ऐसी ही एक बड़ी घटना 'एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस' भी थी। यहाँ पाठकों के लिए इस सम्मेलन की एक झलक पेश की जा रही है:

एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस (ARC) 23 मार्च - 2 अप्रैल 1947

भारत की अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ने 'एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया था, जिसमें 34 अलग-अलग समूहों के 193 प्रतिनिधि और 51 पर्यवेक्षक शामिल हुए थे। इनमें इंडोनेशिया, बर्मा, सीलोन, मलाया, अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, फ़िलिपींस, वियतनाम, फ़िलीस्तीन, मिस्र, तुर्की, जॉर्जिया, कज़ारव्स्तान, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अन्य देश शामिल थे।

भारत की लंबी अँधेरी रात अब ख़त्म हो रही है। हम भाग्यवादी थे। हमारा मानना था कि हमारा ग़ुलाम बने रहना और हमारा शोषण होना हमारी क़िस्मत थी; कि हम पर दूसरों का दबदबा रहेगा और हम उनके अधीन ही रहेंगे। अफ़सोस! अफ़सोस! अफ़सोस! कि हमारी ऐसी हालत थी; लेकिन अब नहीं, कल की सुबह से नहीं; बल्कि, इस घड़ी से ही, कि अब हम इस जंज़ीर से आज़ाद हो रहे हैं। ... साथी एशियाई लोगो, जैसा कि मैंने पहले आपको संबोधित किया था - मेरे साथियो, मेरे अपनों - जागो; याद रखो कि अँधेरे की रात ख़त्म हो चुकी है। आओ, हम सब - पुरुष और महिलाएँ - मिलकर नयी सुबह की ओर बढ़ें।

- सरोजिनी नायडू, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष।

मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद प्रतिनिधि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं - भले ही हमें जापान और कोरिया के, जिनके प्रतिनिधि आज यहाँ नहीं हैं, इसमें शामिल न हो पाने का अफ़सोस है, - और अगर हम पर्यवेक्षकों को भी जोड़ लें, तो यह सम्मेलन पूरी दुनिया के और अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा।

- सर श्री राम, अध्यक्ष, स्वागत समिति, ARC का स्वागत भाषण।

इंडोनेशिया

प्रारंभिक निवासी और शुरुआत, तथा धर्म एवं व्यापार का संगम

इंडोनेशियाई द्वीपसमूह (अनेक द्वीपों का एक समूह) में मनुष्य की बसाहट का इतिहास सैकड़ों, हज़ारों वर्ष पुराना है। आधुनिक आबादी की नींव ऑस्ट्रोनेशियाई लोगों द्वारा रखी गई, जो इस क्षेत्र में लगभग 2,000 ईसा पूर्व आये। वे अपने साथ कृषि कौशल, समुद्री यात्रा की उन्नत क्षमताएँ, और धान की खेती का ज्ञान लेकर आये। उन्होंने तटीय गाँव स्थापित किए जो अंततः परिष्कृत समुद्री राज्यों में विकसित हुए। इंडोनेशिया का भूगोल – महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरूमध्य को पार करता हुआ – इसे चीन, भारत और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला एकमात्र व्यापारिक केंद्र बनाता है। इस रणनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक व्यापार के साथ आने वाली बदलावों की बयार ने इस भूमि की स्थानीय संस्कृति और विश्वास प्रणालियों को लगातार नये रूपों में ढाला। पहले भारतीय व्यापारी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म लाये, और फिर फ़ारस और चीन के मुस्लिम व्यापारियों ने इस भूमि के लोगों तक इस्लाम को पहुँचाया। 16वीं शताब्दी तक, इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया, जिसने मलक्का, असेह और डेमक जैसे शक्तिशाली सल्तनतों को जन्म दिया।

उपनिवेशीकरण और उपनिवेश-विरोधी संघर्ष
आकर्षक मसाला व्यापार (विशेष रूप से जायफल और लौंग) से आकर्षित होकर, यूरोपीय शक्तियाँ 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पहुँचीं।

- डच ईस्ट इंडीज: डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) ने व्यवस्थित रूप से व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, और 19वीं शताब्दी तक डच सरकार ने डच ईस्ट इंडीज की स्थापना करके इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने खेती प्रणाली में बदलाव (अनिवार्य नकदी फ़सल उत्पादन), शोषण और राजनीतिक विखंडन जैसी दमनकारी आर्थिक प्रणालियाँ लागू कीं।
- राष्ट्रवादी जागृति: 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक एकीकृत इंडोनेशियाई पहचान का जन्म हुआ, जो 1928 की 'युवा प्रतिज्ञा' (Sumpah Pemuda) से प्रेरित थी, जिसने एक मातृभूमि, एक राष्ट्र और एक भाषा (बहासा इंडोनेशिया) की घोषणा की।

जापानी क़ब्ज़ा और स्वतंत्रता: जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध (1942-1945) के दौरान द्वीपों पर क़ब्ज़ा कर लिया, जिससे डच अजेयता का भ्रम टूट गया। जापान के आत्मसमर्पण के बाद राष्ट्रवादी नेताओं सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की। लौटती डच सेनाओं के ख़िलाफ़ चार साल तक एक भीषण राजनयिक और गुरिल्ला युद्ध चला, जब तक कि नीदरलैंड ने 1949 में आधिकारिक रूप से इंडोनेशियाई संप्रभुता को मान्यता नहीं दे दी।

स्वतंत्रता के बाद के युग: सुकर्णो से सुहार्तो तक

सुकर्णो का शासन (1945-1967) इंडोनेशिया के करिश्माई प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सुकर्णो ने राष्ट्र-निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और एक अत्यंत विविधतापूर्ण आबादी को पंचशील (पाँच सिद्धांत) के राष्ट्रीय दर्शन के तहत एकजुट किया। वैश्विक परिदृश्य में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया और 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन की मेजबानी की, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी (PKI) इंडोनेशिया में बहुत मज़बूत थी और देश समाजवादी सिद्धांतों पर विकसित हो रहा था। हालाँकि, 1960 के दशक के मध्य तक, आर्थिक समस्याएँ विकराल हो गईं क्योंकि सुकर्णो ने स्पष्ट रूप से सोवियत गुट का पक्ष ले लिया। इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ रही थी जिसके इंडोनेशिया की सेना के साथ मतभेद उत्पन्न हो गए जिसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। पश्चिमी शक्तियों और अमेरिकी सीआईए ने सुकर्णो शासन को अस्थिर करने के लिए अपनी चालें चलीं। सीआईए ने 1950 के दशक के अंत में इन विद्रोहियों को धन और आधुनिक स्वचालित हथियार, यहाँ तक कि भाड़े के अमेरिकी और ताइवानी पायलटों द्वारा संचालित B-26 बमवर्षकों का एक स्वतंत्र बेड़ा भी मुहैया कराया। अपने प्रयासों में विफल होने पर, अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और इंडोनेशियाई सेना के दक्षिणपंथी नेतृत्व को सीधी सहायता देनी शुरू कर दी। इसके कारण एक ख़ूनी तख्तापलट हुआ, जो विफल रहा लेकिन सेना के जनरल सुहार्तो ने सुकर्णो से सत्ता ले ली, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट-विरोधी सफ़ाया अभियान चला, जिसमें लगभग दस लाख लोग मारे गए।

सुहार्तो ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा को पश्चिमी वैश्विक बाजारों की ओर मोड़ दिया। सुहार्तो के शासन के तहत 1967 से 1998 तक, लगभग तीन दशकों तक इंडोनेशिया में स्थिति राजनीतिक रूप से स्थिर रही, लेकिन दो अलग-अलग छोरों पर ग़रीबी और समृद्धि दोनों बढ़ती चली गई और उनके बीच का अंतर चौड़ा होता गया।

आधुनिक इंडोनेशिया: जनसांख्यिकी, राजनीतिक प्रणाली व राजनीतिक अर्थव्यवस्था

जनसांख्यिकी: इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है (28 करोड़ से अधिक लोग) और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम-बहुल आबादी (लगभग 87%) रहती है। यह अत्यंत विविधतापूर्ण देश है, जो 17,000 से अधिक द्वीपों में फैला हुआ है और जहाँ 300 से अधिक विशिष्ट जातीय समूह हैं। इनमें जावानी लोगों का समूह सबसे बड़ा है।

राजनीतिक व्यवस्था: आज इंडोनेशिया एक जीवंत, स्थिर, राष्ट्रपति-शासित प्रतिनिधिक गणराज्य है। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। 1998 के बाद लागू व्यापक विकेंद्रीकरण नीतियों के कारण सत्ता का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय सरकारों की ओर स्थानांतरित हुआ है। वर्तमान राजनीतिक ढाँचा सहमति-निर्माण को महत्व देता है, हालाँकि इसे अक्सर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी और मध्यमार्गी इस्लामी दलों के बीच जटिल गठबंधनों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था: दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जी-20 के सदस्य के रूप में इंडोनेशिया मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पाम ऑयल, कोयला, तथा निकेल जैसे रणनीतिक खनिजों पर निर्भर है,

जो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। हाल में देश ने कच्चे माल के घरेलू प्रसंस्करण (डाउनस्ट्रीमिंग) और बड़े पैमाने पर बुनियादी संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

वैश्विक उपस्थिति: ब्रिक्स, बीआरआई और ग्लोबल साउथ
इंडोनेशिया जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना और वह इसका पहला दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य है। इस क़दम से जकार्ता को न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वैकल्पिक विकास वित्तपोषण तक पहुँच मिली है, पश्चिमी वित्तीय अस्थिरता के विरुद्ध संतुलन बनाने का अवसर मिला है, और क्षेत्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को कम करने की सहूलियत मिली है। पिछले एक दशक में व्यापार और शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी चीन इंडोनेशिया के बहुत क़रीब आ गया है। अभी 20,000 इंडोनेशियाई छात्र चीन में अध्ययन कर रहे हैं। BRI के तहत चीन ने जकार्ता से बांडुंग तक हाई-स्पीड ट्रेन का निर्माण किया है। लेकिन साथ ही, इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंध भी बनाये रखे हैं और उसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं।

BRICS

ब्रिक्स के सदस्य देशों की संक्षिप्त जानकारी

ब्रिक्स देशों से संबंधित आँकड़ों का योग

ब्रिक्स देश	जनसंख्या	क्षेत्रफल (वर्गकिमी)	निर्यात (B$)	आयात (B$)	जीडीपी (T$)
ब्राज़ील	213,421,037	8,515,767	339.695	252.710	2.191
रूस	146,028,325	17,098,246	492.314	293.497	2.072
भारत	1,428,627,663	3,287,590	431.412	672.140	3.638
चीन	1,404,890,000	9,706,761	3379.314	2557.497	18.270
दक्षिण अफ्रीका	63,015,904	1,221,031	110.608	107.123	0.380
इजिप्ट	107,868,296	1,002,450	42.553	84.218	0.396
इथियोपिया	135,500,000	1,104,300	2.859	17.050	0.119
ईरान	92,417,681	1,648,195	80.900	58.726	0.405
सउदी अरब	33,702,731	2,149,690	320.180	206.940	1.219
यूएई	11,027,129	83,600	570.245	470.536	0.514
इंडोनेशिया	288,315,089	1,904,569	258.774	221.886	1.371
ब्रिक्स का योग	3,524,813,859	47,722,199	6028.854	4942.323	30.575
वैश्विक योग	8 बिलियन	130 मिलियन	25 ट्रिलियन	23 ट्रिलियन	107 ट्रिलियन
ब्रिक्स देशों का %	44%	37%	24%	21%	29%

नोट: जनसंख्या और क्षेत्रफल के आँकड़े वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। निर्यात, आयात और जीडीपी के आँकड़े वर्ल्ड इन्टेग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन (WITS) से लिए गए हैं।

ब्राज़ील

राजधानी	ब्रासीलिया
आधिकारिक भाषाएँ	पुर्तगाली
राजनीतिक व्यवस्था	संघीय राष्ट्रपति गणराज्य
राष्ट्रपति	लुइज़ इनसिओ लूला डा सिल्वा
जनसंख्या	213,421,037
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र - लैटिन अमेरिका पड़ोसी देश - अर्जेन्टीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, पेरू, वेनेज़ुएला कुल क्षेत्रफल - 8,515,767 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात - 434.435 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात - 697.745 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी - 41.53 खरब अमेरिकी डॉलर

रूस

राजधानी	मास्को
आधिकारिक भाषाएँ	रूसी
राजनीतिक व्यवस्था	राष्ट्रपति गणराज्य
राष्ट्रपति	व्लादीमिर पुतिन
जनसंख्या	146,028,325
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र - यूरेशिया पड़ोसी देश - नॉर्वे, फ़िनलैंड, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाखस्तान, चीन, मंगोलिया कुल क्षेत्रफल - 17,098,246 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात - 492.314 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात - 293.497 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी - 26.56 खरब अमेरिकी डॉलर

भारत

राजधानी	नयी दिल्ली
आधिकारिक भाषाएँ	हिन्दी/अँग्रेज़ी
राजनीतिक व्यवस्था	संघीय संसदीय गणराज्य
प्रधानमंत्री	नरेंद्र मोदी
जनसंख्या	1,428,627,663
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र - दक्षिण एशिया पड़ोसी देश - बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका कुल क्षेत्रफल - 32,87,590 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात - 434.435 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात - 697.745 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी - 41.53 खरब अमेरिकी डॉलर

चीन

राजधानी	बीजिंग
आधिकारिक भाषाएँ	चीनी
राजनीतिक व्यवस्था	कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था
राष्ट्रपति	शी जिनपिंग
जनसंख्या	1,404,890,000
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र - दक्षिण एशिया पड़ोसी देश - रूस, भारत, उत्तरी कोरिया, कज़ाख्स्तान, किरगिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम। कुल क्षेत्रफल - 9,706,761 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात - 33.80 खरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात - 25.57 खरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी - 182.70 खरब अमेरिकी डॉलर

दक्षिण अफ्रीका

राजधानी	प्रिटोरिया
आधिकारिक भाषाएँ	12 अफ्रीकी भाषाएँ
राजनीतिक व्यवस्था	कार्यपालक राष्ट्रपति प्रणाली के साथ एकात्मक संसदीय गणराज्य
राष्ट्रपति	सिरिल रामाफोसा
जनसंख्या	63,015,904
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र - अफ्रीका प्रमुख पड़ोसी देश - नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बॉब्वे , मोज़ाम्बिक, एसवातिनी कुल क्षेत्रफल - 1,221,037 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात - 110.608 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात - 107.123 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी - 379.964 अरब अमेरिकी डॉलर

मिस्र

राजधानी	काहिरा
आधिकारिक भाषाएँ	अरबी
राजनीतिक व्यवस्था	अधिनायकवादी शासन के अंतर्गत एकात्मक अर्द्ध-राष्ट्रपति शासित गणराज्य
राष्ट्रपति	अब्देल फ़ताहअल-सिसी
जनसंख्या	107,868,296
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – उत्तर-पूर्वी अफ्रीका प्रमुख पड़ोसी देश – लीबिया, सूडान, फ़िलीस्तीन कुल क्षेत्रफल – 1,002,450 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 42.553 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 84.218 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 395.645 अरब अमेरिकी डॉलर

इथियोपिया

राजधानी	एडिस अबाबा
आधिकारिक भाषाएँ	एम्हरिक/ओरोमो/सोमाली
राजनीतिक व्यवस्था	अधिनायकवादी शासन के अंतर्गत संघीय संसदीय गणराज्य
राष्ट्रपति	ताये अत्सके सेलासिए
जनसंख्या	135,500,000
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – पूर्वी अफ़्रीका प्रमुख पड़ोसी देश – इरिट्रिया, डिबौटी, सोमालिया, केन्या, सूडान कुल क्षेत्रफल – 1,104,300 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 2.859 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 17.050 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 119.03 अरब अमेरिकी डॉलर

ईरान

राजधानी	तेहरान
आधिकारिक भाषाएँ	फ़ारसी
राजनीतिक व्यवस्था	अधिनायकवादी तानाशाही के अंतर्गत एकात्मक राष्ट्रपति शासित धार्मिक इस्लामिक गणराज्य
राष्ट्रपति	मोज्तबा ख़ामेनेई
जनसंख्या	92,417,681
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – मध्य एशिया प्रमुख पड़ोसी देश – इराक, तुर्किए, आर्मीनिया, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान कुल क्षेत्रफल – 1,648,195 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 80.900 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 58.726 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 405.293 अरब अमेरिकी डॉलर

सऊदी अरब

राजधानी	रियाध
आधिकारिक भाषाएँ	अरबी
राजनीतिक व्यवस्था	एकात्मक इस्लामिक निरंकुश राजतंत्र
राष्ट्रपति	सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सउद
जनसंख्या	33,702,731
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – पश्चिम एशिया प्रमुख पड़ोसी देश – जार्डन, इराक, कुवैत, क़तर, यूएई, ओमान, यमन कुल क्षेत्रफल – 2,149,690 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 320.180 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 206.940 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 12.19 खरब अमेरिकी डॉलर

संयुक्त अरब अमीरात

राजधानी	अबू धाबी
आधिकारिक भाषाएँ	अरबी
राजनीतिक व्यवस्था	संघीय अर्द्ध-राष्ट्रपति शासित अर्द्ध-सवैधानिक राजतंत्र
राष्ट्रपति	मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान
जनसंख्या	11,027,129
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – पश्चिम एशिया प्रमुख पड़ोसी देश – सउदी अरब, ओमान कुल क्षेत्रफल – 83,600 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 570.245 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 470.536 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 513.546 अरब अमेरिकी डॉलर

इंडोनेशिया

राजधानी	जकार्ता
आधिकारिक भाषाएँ	इंडोनेशियन
राजनीतिक व्यवस्था	एकल राष्ट्रपति शासित गणराज्य
राष्ट्रपति	प्रबोओ सुबियांतो
जनसंख्या	288,315,089
भूगोल	भौगोलिक क्षेत्र – दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख पड़ोसी देश – मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर-लेस्ते कुल क्षेत्रफल – 1,904,569 वर्ग किमी
अर्थव्यवस्था	कुल निर्यात – 258.774 अरब अमेरिकी डॉलर कुल आयात – 221.886 अरब अमेरिकी डॉलर नॉमिनल जीडीपी – 13.71 खरब अमेरिकी डॉलर

सहयोगी देश

बेलारूस
बोलीविया
क्यूबा
कज़ाख्स्तान
मलेशिया

नाइजीरिया
थाइलैंड
युगांडा
उज़्बेकिस्तान
वियतनाम

इन सहयोगी (पार्टनर) देशों के बारे में जानकारियाँ न्यूज़लेटर के आगे के अंकों में उपलब्ध करायी जाएँगी।

हिरोशिमा का बच्चा

मैं हर दरवाज़े पर आता हूँ
पर मेरी मौन आहट कोई नहीं सुन पाता
मैं दस्तक देता हूँ, फिर भी दिखाई नहीं देता
क्योंकि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मैं मर चुका हूँ

मैं तो केवल सात वर्ष का था, जब मैं मरा
बहुत पहले, हिरोशिमा में
अब भी मैं सात का ही हूँ, जैसा तब था
जब बच्चे मर जाते हैं, वे बड़े नहीं होते

लपटों के भँवर ने मेरे बाल झुलसा दिए
मेरी आँखों की रोशनी मद्धिम पड़ गई,
मेरी आँखें अंधी हो गईं
मृत्यु आयी और मेरी हड्डियों को धूल में बदल गई
और वह धूल हवा में बिखर गई

मुझे न फल चाहिए, न चावल
मुझे न मिठाइयाँ चाहिए, न रोटी
मैं अपने लिए कुछ नहीं माँगता
क्योंकि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मैं मर चुका हूँ

मुझे बस इतना चाहिए कि शांति के लिए
तुम आज लड़ो, तुम आज लड़ो
ताकि इस दुनिया के बच्चे
जी सकें, बड़े हो सकें, हँस सकें और खेल सकें

- नाज़िम हिकमत

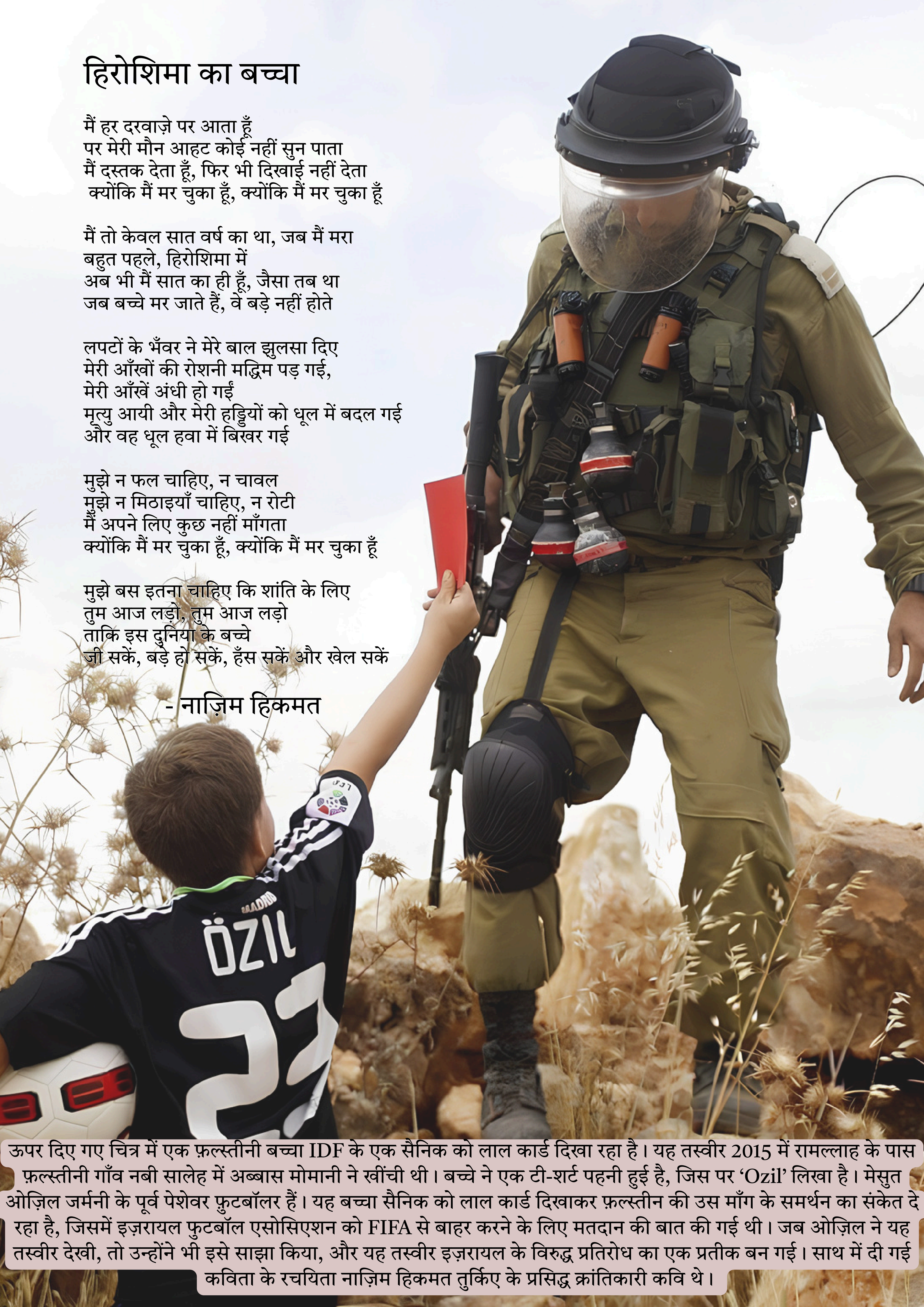

ऊपर दिए गए चित्र में एक फ़लस्तीनी बच्चा IDF के एक सैनिक को लाल कार्ड दिखा रहा है। यह तस्वीर 2015 में रामल्लाह के पास फ़लस्तीनी गाँव नबी सालेह में अब्बास मोमानी ने खींची थी। बच्चे ने एक टी-शर्ट पहनी हुई है, जिस पर 'Ozil' लिखा है। मेसुत ओज़िल जर्मनी के पूर्व पेशेवर फ़ुटबॉलर हैं। यह बच्चा सैनिक को लाल कार्ड दिखाकर फ़लस्तीन की उस माँग के समर्थन का संकेत दे रहा है, जिसमें इज़रायल फुटबॉल एसोसिएशन को FIFA से बाहर करने के लिए मतदान की बात की गई थी। जब ओज़िल ने यह तस्वीर देखी, तो उन्होंने भी इसे साझा किया, और यह तस्वीर इज़रायल के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई। साथ में दी गई कविता के रचयिता नाज़िम हिकमत तुर्किए के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि थे।